Tc.No. : GUJHIN00722

पेज: 4, मुल्य 1 रु.

क्रांति समय

संस्थापक / संपादक : सुरेश मौर्या

E-mail: krantisamay@gmail.com, www.krantisamay.com

वर्ष: 1 अंक: 34 , 28 अक्टुबर, शनिवार 2017, सूरत, हिन्दी दैनिक मो. 9879141480

4 ओ ब्लॉक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष, सचीन रेल्वे स्टेशन के पास, सूरत-गुजरात

सार समाचार

यूपी बोड की परीक्षा समय सारिणी घोषित

इलाहाबाद। माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2018 का कार्यक्रम (समय सारिणी) घोषित कर दी गई है। यह परिक्षाएं 6 फरवरी से शूरू होंगी। हाईस्कूल की परीक्षा 22 फरवरी तक और इंटर की परीक्षा 10 मार्च को खत्म होंगी। बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने शुक्रवार दोपहर परीक्षा कार्यक्रमों की घोषणा की। बोर्ड ऑफिस में सचिव नीना श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को बताया कि यूपी बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा 14 दिन में जबकि इंटर की 25 दिनों में पूरी होगी। उनके मुताबिक परीक्षाएं पूर्व की तरह दो पालियों में ही होंगी। दो पालियों में होनेवाली परीक्षा की पहली पाली सुबह 7.30 से 10.45 बजे जबकि दूसरी पाली दिन 2 से 5.15 बजे तक होगी।

12 वीं बोर्ड के लिए जारी किया मॉडल प्रश्नपत्र, मिलेगी बदले हुए परीक्षा पैटर्न की जानकारी

नई दिल्ली। सीबीएसई ने आगामी 2018 बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। जहां मार्च में परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है वहीं बदले हुए परीक्षा पैटर्न की जानकारी विद्यार्थियों को मॉडल प्रश्नपत्र 2017-18 के माध्यम से दी जा रही है। इसके अलावा मार्किंग स्कीम की भी जानकारी विद्यार्थी प्रश्नपत्र के माध्यम से ले पायेंगे। 2009 के बाद सीबीएसई ने 12वीं के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। मल्टीपल च्वाइस के प्रश्नों को हटा दिया गया है। अब शॉर्ट और लांग टाइप प्रश्न ही रहेंगे।

मार्किंग स्कीम की भी बोर्ड ने दी जानकारी

बदले हुए पैटर्न की जानकारी छात्रों को एक महीने पहले ही सीबीएसई ने दी है। हर साल नवंबर के अंतिम सप्ताह में बोर्ड मॉडल प्रश्नपत्र जारी करता था। लेकिन इस बार अक्टूबर में ही छात्रों को दे दिया गया है। मॉडल प्रश्नपत्र के साथ बोर्ड ने मार्किंम स्कीम की भी जानकारी विद्यार्थियों को दी है। इससे किस प्रश्न पर कितने अंक होंगे, इसकी जानकारी विद्यार्थियों को मिल जायेगी।

सब्जेक्टिव से जोड़ने की बोर्ड की तैयारी

12वीं में विद्यार्थी अधिक से अधिक स्कूल की पढ़ाई से जुड़ें, कांसेप्ट क्लियर हो, इसके लिए 12वीं के पैटर्न में बदलाव किया गया है। प्रश्नपत्र में सब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या अधिक की गयी है।

तैयारी में मिलेगी मदद

मॉडल प्रश्नपत्र मिलने से विद्यार्थी अपनी तैयारी उसी के अनुसार कर पायेंगे। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर मॉडल प्रश्नपत्र डाल दिया है। इससे विद्यार्थी अपनी तैयारी पहले से कर पायेंगे। इस मॉडल प्रश्नपत्र की तैयारी का फायदा छात्रों को सेंटअप परीक्षा में भी होगा। दिसंबर मे सेंटअप परीक्षा होने के पहले विद्यार्थी प्रश्नपत्र से तैयारी कर पायेंगे।

प्रश्नपत्र में ये होगा बदलाव

- तीन घंटे की परीक्षा होगी
- एक अंक के सात प्रश्न होंगे। हर प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में देना होगा
- दो पैटर्न पर प्रश्न रहेंगे। शॉर्ट और लांग
- हर प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य होगा
- मल्टीपल च्वाइस के प्रश्न को हटा दिया गया है
- कुछ विषयों में पांच तो कुछ विषयों में आठ अंक के भी प्रश्न पूछे गये हैं
- आठ अंक के प्रश्नों को पहली बार जोड़ा गया है। इसका उत्तर 350 शब्दों में देना होगा।

हाईकोर्ट ने की स्वामी की याचिका खारिज

सुनंदा पुष्कर मौत मामला

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई थी। साथ ही अदालत ने उनकी जनहित याचिका को राजनीतिक हित याचिका का एक स्पष्ट उदाहरण करार दिया। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आई एस मेहता की पीठ ने कहा कि स्वामी की याचिका पर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई नहीं हो सकती। पीठ ने यह भी कहा कि अदालत के समक्ष जो भी तय रखे गए उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि विशेष जांच दल द्वारा की जा रही जांच को किसी भी पक्ष द्वारा प्रभावित किया गया है। अदालत ने कहा कि उसका यह भी मानना है कि स्वामी ने वह जानकारी छिपाई जिसके आधार पर उन्होंने थरूर और दिल्ली पुलिस के खिलाफ आरोप लगाए थे।

बेड के मातृ-शिशु रेफरल सेंटर के शुभारंभ

लोहिया संस्थान-अस्पताल का समझौता नहीं, विलय होगा : सीएम

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और लोहिया अस्पताल के विलय पर मुहर लगा दी है। उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए साफ कर दिया कि अब समझौता नहीं बल्कि पूरी तरह विलय किया जाएगा। वहीं गोमतीनगर विस्तार में बने मातृ एवं शिशु रेफरल चिकित्सालय को अब पूर्व मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त के नाम पर जाना जाएगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को शहीद पथ पर नेशनल हेल्थ मिशन के सहयोग से बने 200 बेड के मातृ-शिशु रेफरल सेंटर के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। संबोधन से पहले उन्होंने अस्पताल का जायजा लिया। उन्होंने मंच से ही लोहिया संस्थान और लोहिया अस्पताल विलय पर मोहर लगाकर लम्बे समय से चल रहे कयासों-विवादों पर विराम लगा दिया।

इस मौके पर सीएम ने कहा कि जब मैं प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखता हूं तो लगता है कि सुविधाएं हम दे सकते हैं लेकिन डॉक्टर कहां से आएंगे? बुंदेलखंड गया था, वहां पीएचसी-सीएचसी में डॉक्टर बहुत कम हैं। पश्चिमी और पूर्वी यूपी का भी यही हाल है। हमारा प्रयास है कि हर कमिश्निरी में एक मेडिकल कालेज जरूर हो। पहले चरण में मंडल, दूसरे चरण में जिलों पर मेडिकल कालेज खोलेंगे।

सीएम ने भावी डॉक्टरों से अपील की गांवों में एक-दो या तीन साल तक अपनी सेवाएं जरूर दें। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों के लिए छात्रावास और डॉक्टरों-स्टाफ के लिए आवास की मांग भी पूरी करने का आश्वासन दिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन ने इस अस्पताल का नाम यूपी के पूर्व सीएम रामप्रकाश गुप्त के नाम पर रखने का आग्रह किया था। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने कहा ये बाल महिला रेफ़रल सेंटर प्रदेश में अपने किस्म का पहला संस्थान हैं। यहां सभी आधुनिक सुविधा एक छत के नीचे मिलेंगी। फिलहाल 60 बेड से शुरुआत की गई है। एक माह में आईसीयू भी शुरू हो जाएगा। आगामी सत्र से नोएडा में बने मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। संस्थान के निदेशक प्रो. दीपक मालवीय ने मुख्यमंत्री से 500 बेड सुपर स्पेशियलिटी सेंटर के लिए सहयोग का अनुरोध भी किया।

स्वास्थ्य विभाग-चिकित्सा शिक्षा में खींचतान

लोहिया संस्थान में एमबीबीएस की मान्यता मिलने के बाद लोहिया अस्पताल के विलय की कवायद शुरू हुई लेकिन सियासी बयानबाजी ने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी थी। कुछ अधिकारी व नेता विलय के बजाए समझौते के आधार पर चलाने के पक्षधर थे। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग में खींचतान की स्थिति बनी हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

कश्मीरी पंडितों क झटका, पुनर्विचार याचिका खारिज

नई दिल्ली। कश्मीरी पंडितों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रूट्स इन कश्मीर नाम की संस्था की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 1989-90 में कश्मीरी पंडितों की हत्या की 215 घटनाओं की जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने रूट्स इन कश्मीर संस्था कि पुनर्विचार याचिका पर इन चेंबर सुनवाई के बाद उसको ख़ारिज कर दिया। रूट्स इन कश्मीर संस्था ने सुप्रीम कोर्ट के इसी साल 24 जुलाई के कोर्ट के आदेश को चुनोती दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 27 साल पहले हुई इस घटना के जांच के आदेश नही दे सकते। रूट्स इन कश्मीर संस्था ने अपनी पुनर्विचार में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में SIT जांच के आदेश दिए है। संस्था ने कहा था कि अगर 33 साल पुराने सिख विरोधी दंगे मामले में कोर्ट सभी मामलों का स्कूटनी कर के बंद मामलों को फिर से खोलने का और जांच के आदेश दे सकता है तो 27 साल पुराने कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले में क्यों नहीं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 24 जुलाई को रूट्स इन कश्मीर संस्था की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने 1989-90 में कश्मीरी पंडितों की हत्या की 215 घटनाओं की जांच की मांग की थी।

उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि आप 27 साल से कहां थे।अब इतने सालों बाद इन मामलों में सबूत कैसे मिलेंगे? तब संस्था की तरफ से कहा गया कि संस्था से जुड़े लोग अपनी जान बचा कर भागे थे, लंबे समय तक अपने आप को दोबारा खड़ा करने के लिए संघर्ष करते रहे।

यूपी निकाय चुनाव का ऐलान:

3 चरणों में होंगे मतदान, 1 दिसंबर को मतगणना

लखनऊ। यूपी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह चुनाव तीन चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण का मतदान मतदान 22 नवंबर, दूसरे चरण का 26, नवंबर और तीसरे चरण का 29 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना पूरे प्रदेश में एक साथ 1 दिसंबर को सुबह 8:00 बजे से शुरू होगी। राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को चुनाव कार्यक्रम का प्रस्ताव भेज दिया है। आयोग अब इसके आधार पर अधिसूचना जारी करेगा। यूपी में इस बार 653 निकायों में 12007 वार्डों में चुनाव होगा। मेयर की 16 सीटों, पालिका परिषद चेयरमैन की 199 तथा नगर पंचायत की 429 सीटों पर मतदान होना है। राज्य निवार्चन आयुक्त एस के अग्रवाल ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों को नहीं तैनात किया जाएगा। राज्य पुलिस बल की ही तैनाती रहेगी। अग्रवाल ने बताया कि 16 नगर निगमों, 198 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायतों के चुनाव की मतगणना एक दिसंबर को होगी। उन्होंने बताया कि कुल 36, 269 मतदान बूथ और 11, 389 मतदान केंद्र बनाये जायेंगे। कुल 3.32 करोड़ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। अलग अलग चरणों का ब्यौरा देते हुए अग्रवाल ने बताया कि पहले चरण में 24 जिलों में मतदान होगा। इसमें पांच नगर निगम, 71 नगर पालिका परिषद और 154 नगर पंचायतें शामिल हैं। दूसरे चरण में 25 जिलों में मतदान होगा। इसमें छह नगर निगम, 51 नगर पालिका परिषद और 132 नगर पंचायत शामिल हैं। तीसरे चरण में 26 जिलों में मतदान होगा। इसमें पांच नगर निगम, 76 नगर पालिका परिषद और 152 नगर पंचायत शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी हो चुकी है। इस बार मतदाताओं को आयोग की वेबसाइट पर मोबाइल नंबर पंजीकत करने का विकल्प दिया गया है। सभी सूचनाएं और परिणाम मोबाइल नंबर पर तत्काल उपलब्ध करा दी जाएंगी। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है। अग्रवाल ने बताया कि दस प्रतिशत पोलिंग बूथ अत्यंत संवेदनशील श्रेणी में रखे गये हैं। वहां चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी और सीसीटीवी लगाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि नगर निगम के मेयर और पार्षद पदों के चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से होंगे, जबकि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्षों एवं सदस्यों का निवार्चन बैलेट पेपर के माध्यम से होगा।

अज्ञात के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया

साइबर क्राइम के जाल में फंसा हवलदार

नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच कर रही है जांच राजधानी में रहने वाले आमलोग तो साइबर क्राइम के जाल में फंस ही रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम करने वाले धंधेबाज अब पुलिसकर्मियरे को भी शिकार करने से गुरेज नहीं कर रहे। ऐसे ही एक मामले में विकासपुरी स्थित तीसरी बटालियन में तैनात एक हवलदार से एटीएम कार्ड रिन्यू करने के नाम पर ठगी कर ली गई। पीड़ित हवलदार ने इसकी शिकायत जुलाई माह में क्राइम ब्रांच से की लेकिन चार महीने बाद अज्ञात के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी दूर उसकी पहचान भी उजागर नहीं हो सकी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हवलदार जगमाल सिंह के पास जुलाई महीने में एक कॉल आयी थी। जिसमें कॉल करने वाले दावा किया कि वह बैंक मैनेजर बोल रहा है और आपके पास बैक एटीएम कार्ड की वैधता खत्म हो गई है। यह सुनकर हवलदार ने उस शख्स से बैंक जाकर कार्ड रिन्यू कराने की बात कही, लेकिन उस व्यक्ति ने हवलदार को यह झांसा दिया कि वह यदि चाहे तो वह बिना बैंक गए उसके कार्ड को रिन्यू कर देगा। इसके बाद हवलदार एटीएम कार्ड रिन्यू कराने के लिए तैयार हो गया और उसने कथित बैंक मैनेजर द्वारा पूछे गए एटीएम कार्ड का डिटेल बता दिया। कुछ देर बाद हवलदार के मोबाइल पर ओटीपी मैसेज आया, जिसके बारे में भी पीड़ित ने अज्ञात शख्स को जानकारी दे दी। पीड़ित ने पुलिस के समक्ष दावा किया कि ओटीपी मैसेज बताने के बाद ही उसके एकाउंट से करीब 14 हजार रपए कट गए और उसने जब इस बाबत पूछा तब उसे कहा गया कि उसके एकाउंट से रपए नए कार्ड में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद में उस शख्स ने फोन काट दिया।

पीड़ित हवलदार को जब ठगी का अहसास हुआ तब उसने फौरन अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कराया और उसने इस बारे मे पुलिस को जानकारी दी, लेकिन ठगी का यह मुकदमा दर्ज किए जाने में काफी वक्त लग गया।

लगातार बढ़ रहीं वारदात :

राजधानी में साइबर क्राइम की वारदातें लगातार बढ़ रहीं है और दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम करने वाले आरोपियों पर नकेल कसने के लिए कोई भी पुख्ता कदम उठा नहीं रही है।

एक अन्य मामले में पटेलनगर की रहने वाली भानू गुप्ता ने भी इस तरह की शिकायत पुलिस से की है। पीड़िता ने दावा किया कि वह एक बुजुर्ग महिला है और जुलाई महीने में ही एक अज्ञात शख्स ने उसे एटीएम कार्ड ब्लॉक होने के नाम पर ओटीपी तथा सीवीवी की जानकारी लेकर दो विभिन्न बैंकों से करीब 40 हजार रपए निकाल लिए। पीड़ित महिला ने दावा किया कि उसे वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर यह रकम हासिल हुए थे और धोखाधड़ी करने वालों ने उसकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर दी। पिलहाल क्राइम ब्रांच ने इस बाबत भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पार्टी में दो गुटों में चलीं गोलियां

पुलिस ने पांच को किया गिरफ्तार

पूर्वी दिल्ली। जन्मदिन पार्टी के दौरान दो गुटों में हुए झगड़े में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गोलियां चलाकर जानलेवा हमला किया। न्यू अशोकनगर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के पांच लोगों को हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से दो कट्टे दो कारतूस व एक बाइक बरामद की है। आरोपियों की शिनाख्त अमित निवासी राजपुर लोनी, हरीओम उर्फ करण निवासी कोंडली, अन्नू उर्फ नगमा पत्नी निवासी पुराना कोंडली, संतोश उर्फ सपना निवासी कोडली, सोनू उर्फ अरविंद निवासी खोड़ा कालोनी के रूप में हुई है। पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। घटना थाना न्य अशोकनगर क्षेत्र के कोंडली में हुई थी। जन्मदिन पार्टी के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए और मारपीट हुई।

इसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गोलियां बरसाई। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। गोलियां बरसाने के बाद दोनों पक्षों के लोग मौके से फरार हो गए। बाद में पुलिस की टीम ने वारदात में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

डॉक्टर के घर लाखों की सेंधमारी

नई दिल्ली। जनकपुरी क्षेत्र में चोरों ने डॉक्टर के घर में लाखों की सेंध लगा दी। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे। पुलिस पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश कर रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक डॉ. अश्वनी मेहता (59) परिवार के साथ जनकपुरी क्षेत्र में किराए के मकान में रहते हैं और उत्तमनगर में उनका क्लीनिक है। पुलिस के मुताबिक सुबह अश्वनी क्लीनिक, जबकि परिवार के अन्य सदस्य बाहर किसी काम से चले गए। पीड़ित ने घर जाकर देखा तो गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान इधर-उधर फैला था। पीड़ित के मुताबिक घर से लगभग 3.75 लाख रपए व लगभग तीन लाख के गहने चोरी हुए हैं। पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर चोरों की शिनाख्त की कोशिश कर रही है।

सम विषम योजना लागू करने की तैयारी शुरू करे डीटीसी : गहलोत

नई दिल्ली। प्रदूषण स्तर में भारी बढ़ोतरी के कारण दिल्ली सरकार ने सम विषम परियोजना लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन अफसरों को पत्र लिखकर डीटीसी व परिवहन विभाग को इसकी पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सड़कों पर कारों की संख्या को प्रतिबंधित करने के लिए सम-विषम योजना को फिर से लागू कर सकती है।मंत्री ने दिल्ली परिवहन निगम और अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों को पत्र लिखकर कहा कि जब कभी सम-विषम की घोषणा की जाती है, वे इसे लागू करने को पूरी तरह तैयार रहें। गहलोत ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ने से कई कड़े कदम उठाने होंगे जिसमें सम-विषम योजना भी शामिल है। इसके पूर्व यह योजना वर्ष 2016 में एक जनवरी से 15 जनवरी और फिर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू की गई थी। इस योजना के तहत सम और विषम संख्या वाले वाहन सम विषम तारीखों वाले दिनों में सड़कों पर चलते हैं। वायु प्रदूषण स्तर के 48 घंटे या इससे अधिक समय के लिए आपात श्रेणी में रहने पर इसे लागू किया जा सकता है। चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) को लागू करने का अधिकार रखने वाले पर्यावरण प्रदूषण नियंतणप्राधिकरण (ईपीसीए) ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह आवश्यकता पड़ने पर सम-विषम योजना लागू करने, कारों को सड़कों पर नहीं चलने का आदेश देने और स्कूलों को बंद करने का आदेश देने से हिचकेगा नहीं। ईपीसीए को उच्चतम न्यायालय ने नियुक्त किया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि सम-विषम योजना लागू करने के पूर्व डीटीसी को अतिरिक्त बसों की खरीद करनी होगी। योजना को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती अच्छी तरह विकसित दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के अलावा सार्वजनिक परिवहन की खराब सुविधाएं है। राजधानी में 11 हजार बसों की जरूरत है जबकि डीटीसी के पास 3800 बसें है व दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टीमॉडल ट्रांजिट सिस्टम 1600 बसें चलाता है। ईपीसीए वायु प्रदूषण स्तर के बहुत खराब स्तर तक पहुंचने के बाद बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र को मार्च 2018 तक बंद कर चुका है व डीजल जनरेटरों पर प्रतिबंध लगा चुका है। अब परिवहन मंत्री ने आड इवन योजना लागू करने के पूर्व तैयारी करने का आदेश जारी किया है।

ईर के सामने सिर झुकाने से क्या होगा,
जब ह्रदय ही अशुद्ध हो --गुरु नानक

शी जिनफिंग

पार्टी का 19 वां महाधिवेशन इस मायने में महत्त्वपूर्ण नहीं है कि राष्ट्रपति शी जिनिफंग को सर्वसम्मति से केंद्रीय समिति ने दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया है। ऐसा पहले भी महाधिवेशन में होता रहा है। वहां राष्ट्रपति का 5 वर्षो का एक कार्यकाल होता है और ज्यादातर राष्ट्रपति दो कार्यकाल वाले रहे हैं। महत्त्वपूर्ण इसलिए है कि शी जिनफिंग सर्वशक्तिशाली बनकर उभरे हैं। इस महाधिवेशन में केंद्रीय समिति से लेकर पोलित ब्यूरो तक के चेहरे को देखें तो यह मानना होगा कि इस समय ही नहीं निकट भविष्य में भी कोई नेता उनके आसपास पहुंचने वाला नहीं होगा। वास्तव में उन्हें माओत्से तुंग के समकक्ष खड़ा कर दिया गया है। हालांकि विश्लेषक यह संभावना पहले से व्यक्त कर रहे थे कि वे सर्वशक्तिमान बनकर उभरेंगे और तंग शिआओपिंग की तरह शक्तियां हासिल कर सकते हैं, किंतु वे माओ के कद तक पहुंच जाएंगे इसकी भविष्यवाणी किसी ने नहीं की थी। पिछले तीन दशक से पार्टी महाधिवेशन में पार्टी पोलित ब्यूरो से कुछ वरिष्ठ लोग सेवानिवृत्त किए जाते थे एवं पचास के आसपास के उम्र के कुछ लोग शामिल किए जाते थे। इनमें से ही कोई अगले महाधिवेशन में ब्यूरो की स्थायी समिति में शामिल कर लिया जाता था जिसे भविष्य में पार्टी एवं सत्ता का दावेदार माना जाता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। हां, पोलित ब्यूरो मे ऐसे कुछ लोग हैं, जिनकी उम्र साठ से कम है लेकिन स्थायी समिति में सभी साठ या उससे ऊपर के हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एवं सरकार दोनों का उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुआ है। चीन में कोई इस निर्णय पर खुलकर उंगली उठा नहीं सकता। लेकिन दुनिया यह प्रश्न उठा रही है कि चीन की भावी दिशा क्या होगी? माओ जीवन भर कम्युनिस्ट पार्टी और सत्ता के केंद्र बने रहे। चीन ने विदेश नीति के कई मुद्दों पर जो आक्रामक रवैया अपनाया है, उससे पूरी दुनिया आशंकित है। उसमें एक नेता का सर्वशक्तिमान बनना सबको चिंतित करने के लिए पर्याप्त है। कम्युनिस्ट शासन होते हुए भी एक सामूहिक नेतृत्व का चरित्र चीन में रहा है। शायद आंतरिक औपचारिक विमर्श में कुछ असहमतियां भी उभरतीं हों और उनके बीच से निर्णय लिया जाता रहा हो। यह स्थिति इस समय समाप्त हो गई है। चीन हमारा पड़ोसी ही नहीं, उसके साथ हमारे विवाद भी है। इस नाते भारत में शी के सर्वशक्तिशाली होने से चिंता पैदा होना स्वाभाविक है।

भाजपा और मुख्य विपक्षी

गुजरात विधान सभा चुनाव की घोषणा के साथ सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच चुनावी दंगल के लिए मंच तैयार हो गया। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक प्रदेश में दो चरणों में 9 और 14 दिसम्बर को मतदान होगा और 18 दिसम्बर को हिमाचल प्रदेश के साथ नतीजों की घोषणा की जाएगी। गुजरात में अब तक किसी असरदार क्षेत्रीय दल का उभार नहीं हो पाने के कारण भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। प्रदेश के इस चुनाव को विशेष तौर पर इसलिए महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दोनों यहीं से आते हैं। यहां कई वर्षो से भाजपा की सरकार है, लिहाजा कांग्रेस मानकर चल रही है कि उसे सत्ताजनित आक्रोश का राजनीतिक लाभ मिलेगा। प्रदेश में नये जातीय समीकरण बने हैं जिनका झुकाव कांग्रेस की ओर है। 2014 के लोक सभा चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस भाजपा को मजबूत राजनीतिक चुनौती देने की स्थिति में लग रही है। प्रदेश की राजनीति में तीन युवा नेताओं का उभार हुआ है, जिनमें ओबीसी के नेता अल्पेश ठाकुर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल की कांग्रेस से वार्ता चल रही है। पाटीदारों को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण देने की मांग पर कांग्रेस सहमत हो जाती है तो हार्दिक पटेल कांग्रेस का समर्थन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश में पाटीदार, ओबीसी, दलित और मुसलमानों को लेकर एक नया जातीय समीकरण बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। नतीजों के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये युवा जातीय नेता 1974 के छात्र आंदोलन के इतिहास को दोहरा पाते हैं या नहीं। तब प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट के सवाल पर छात्रों के नवनिर्माण आंदोलन के कारण कांग्रेसी मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल की सरकार को जाना पड़ा था। राहुल प्रदेश की चुनाव सभाओं में लगातार भाजपा के विकास मॉडल, आर्थिक मंदी और जीएसटी के दोषपूर्ण क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा के लिए गुजरात का चुनाव राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि चुनाव नतीजे 2019 के लोक सभा चुनाव को प्रभावित करेंगे। 18 दिसम्बर को पता चल पाएगा कि जनता किसे पसंद करती है और किसे खारिज करती है।

सत्संग

''ईर बड़ा दयालु है,

चित्त का मतलब हुआ विशुद्ध प्रज्ञा व चेतना, जो स्मृतियों से पूरी तरह से बेदाग हो। यहां कोई स्मृति नहीं होती है। हर तरह की बातें कही गई हैं। ''ईर बड़ा दयालु है, ईर प्रेम है, ईर यह है, ईर वह है।' मान लीजिए कि किसी ने भी ये सारी बातें आपसे न कहीं होतीं और आप बिना कुछ सुने या माने बस अपने आसपास की सृष्टि को ध्यान से देखते कि कैसे एक फूल खिलता है, कैसे एक पत्ती निकलती है, कैसे एक चींटी चलती है। अगर आप इन सारी चीजें पर पूरा ध्यान देते तो इस नतीजे पर आपका पहुंचना तो तय था कि इस सृष्टि का स्रेत जो भी है, उसमें अद्भुत इंटेलिजेंस है, वह प्रज्ञावान है। सृष्टि की हर चीज में एक जबरदस्त इंटेलिजेंस है, जो हमारे काफी तेज दिमाग से बहुत परे है। चित्त मन का सबसे भीतरी आयाम है, जिसका संबंध उस चीज से है, जिसे हम चेतना कहते हैं। अगर आपका मन सचेतन हो गया, अगर आपने चित्त पर एक खास स्तर का सचेतन नियंतणप्रा लिया, तो आपकी पहुंच अपनी चेतना तक हो जाएगी।हम लोग जिसे चेतना कह रहे हैं, वो वह आयाम है, जो न तो भौतिक है और न ही विद्युतीय और न ही यह विद्युत चुंबकीय है। यह भौतिक आयाम से अभौतिक आयाम की ओर एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। यह अभौतिक ही है, जिसकी गोद में भौतिक घटित हो रहा है। इस पूरे ब्रह्माण्ड का मुश्किल से दो प्रतिशत या शायद एक प्रतिशत हिस्सा ही भौतिक है, बाकी सब अभौतिक ही है। योगिक शब्दावली में इस अभौतिक को हम एक खास तरह की ध्वनि से जोड़ते हैं। हालांकि आज के दौर में यह समझ बहुत बुरी तरह से विकृत हो चुकी है, इस ध्वनि को हम ''शि-व' कहते हैं। शिव का मतलब है, ''जो है नहीं'। जब हम शिव कहते हैं तो हमारा आशय पर्वत पर बैठे किसी इंसान से नहीं होता। हम लोग एक ऐसे आयाम की बात कर रहे होते हैं, जो है नहीं, लेकिन इसी ''नहीं होने' के अभौतिक आयाम की गोद में ही हरेक चीज घटित हो रही है। तो यह हमारे भीतर मौजूद इंटेलिजेंस व प्रज्ञा का आयाम है, जो एक तरीके से हमारे निर्माण का आधार है। अगर आप रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं, तो कुछ घंटों में रोटी इंसान में बदल जाएगी, क्योंकि यह इंटेलिजेंस व प्रज्ञा आपके और हमारे भीतर मौजूद है। योगिक संस्कृति में बेहद शरारती ढंग से कहा गया है,''अगर आप अपने चित्त को छू लेंगे, अगर आप अपनी इंटेलिजेंस के उस आयाम तक पहुंच जाएंगे, तो ईर भी आपका दास हो जाएगा।

राष्ट्र एक कानून नारा

आईपीसी जो पूरे देश में लागू है, उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के न्यायिक काम में बाधा डालता है, उस पर अधिकतम 6 महीने की सजा या 1000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। लेकिन वर्तमान अध्यादेश जो अब कानून बनने जा रहा है और न केवल कानून बल्कि कठोर कानून बनने जा रहा है। जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। यानी सजा में तीन गुना बढ़ोत्तरी। जबकि जुर्माने की राशि के बारे में फिलहाल कुछ भी स्पष्ट तौर पर बताया नहीं गया है। इसके अलावा सीआरपीसी के अनुच्छेद 191 यह कहता है कि कोई भी अदालत किसी मामले में किसी सरकारी कर्मचारी, मजिस्ट्रेट, जज के बारे में कोई जांच का आदेश या सुनवाई नहीं कर सकती है।

सतीश पेडणेकर

राष्ट्र एक कानून नारा अच्छा लगता है। पर निजी कानून की बात छोड़ दें तो देश में समान आपराधिक कानून तक एक नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि कानून का जो विषय है वो समवर्ती सूची में नहीं है। यानी सभी विधान सभाएं इस पर कानून बना सकती हैं। आईपीसी और सीआरपीसी में 100 से ज्यादा संशोधन राज्य सरकारों ने किए हैं। एक बार फिर संशोधन हुआ है। यह संशोधन आईपीसी और सीआरपीसी में हुआ है। सीआरपीसी में जिसे 1973 में संसद ने बनाया था। और आईपीसी में जो 1860 में बना था। संविधान ने हमारी संसद और विधान सभाओं को आपातकालीन हालात में भी विधायी कार्य करने की अनुमति दी है, जिसमें उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वो अध्यादेश की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार जिस आनन-फानन में अध्यादेश लेकर आई, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। कोई आसमान नहीं टूट रहा था। 7 सितम्बर को जब अध्यादेश लाया गया, जबकि 23 अक्टूबर को विधान सभा का सत्र निर्धारित था। इस पूरे मामले में न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी शामिल है क्योंकि इस अध्यादेश में साफसाफ लिखा है कि इसके बारे में इसमें संविधान के अनुछेद 213 के तहत राष्ट्रपति से अनुमति ली गई है। हम सभी को मालूम है कि राष्ट्रपति केंद्र के आग्रह पर ही किसी कानून की अनुमति देते हैं। आईपीसी जो पूरे देश में लागू है, उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के न्यायिक काम में बाधा डालता है, उस पर अधिकतम 6 महीने की सजा या 1000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। लेकिन वर्तमान अध्यादेश जो अब कानून बनने जा रहा है और न केवल कानून बल्कि कठोर कानून बनने जा रहा है। जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। यानी सजा में तीन गुना बढ़ोत्तरी। जबकि जुर्माने की राशि के बारे में फिलहाल कुछ भी स्पष्ट तौर पर बताया नहीं गया है। इसके अलावा सीआरपीसी के अनुच्छेद 191 यह कहता है कि कोई भी अदालत किसी मामले में किसी सरकारी कर्मचारी, मजिस्ट्रेट, जज के बारे में कोई जांच का आदेश या सुनवाई नहीं कर सकती है, जब तक की संबंधित अधिकारी की राज्य सरकार या केंद्र सरकार से अनुमति नहीं ले ली जाती है। यानी 197 का कानून अदालत के बारे में है और एफआईआर करने से नहीं रोकता। लेकिन इसके बावजूद एक और प्रावधान सीआरपीसी 190 का है, जिसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को जांच का अधिकार दिया गया है। यहां मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में दो तरीके के अपराध के बारे में बात की गई है। संज्ञेय और गैर-संज्ञेय। गैर-संज्ञेय अपराध छोटे अपराधों की श्रेणी में आता है। यानी आपने किसी को थप्पड़ मार दिया। इसमें बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। संज्ञेय अपराध; जिसमें हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे मामले आते हैं। उसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच कर सकता है। इसके अनुच्छेद 156 में अब एक संशोधन राज्य सरकार ने किया है। इसी तरह अनुच्छेद 190 के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि संज्ञेय अपराध के मामले जो उसके संज्ञान में आता है, या कोई शिकायत दर्ज करता है उस मामले में वो जांच का आदेश दे सकता है। राजस्थान के इस कानून ने जो मजिस्ट्रेट और पुलिस को अधिकार दिए गए थे उनको सीमित किया गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं-न-कहीं यह अध्यादेश संवैधानिक नहीं है। क्योंकि यह न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर रहा है। यह तो बात हो गई पुलिस और मजिस्ट्रेट की। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। जिसमें आरोपी की पहचान मीडिया में सार्वजनिक नहीं की जा सकती। प्रिंट नहीं की जा सकती। यानी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में कुछ भी लिखा नहीं जा सकता या प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। यानी मीडिया में यह भी नहीं लिखा जा सकता कि उस व्यक्ति के बारे में सरकार ने अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब यह है कि हम अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं। मेरी समझ में अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो अपने आप में इतना बड़ा अधिकार है कि उसे मैं प्राथमिक स्वतंत्रता कहता हूं। संविधान सभा में भी यह बात कही गई है जब धर्म की स्वतंत्रता पर बात हो रही थी कि धर्म की स्वतंत्रता को लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही निहित है। हाल ही में निजता के अधिकार के मामले में फैसले में जस्टिस होम साहब के 1890 के लेख का जिक्र किया गया, उन्होंने ''विचारों के बाजार' की बात की थी, जिसके अनुसार विचारों को आने दीजिए। और लोगों को उसपर राय बनाने का मौका दीजिए। जो सच है वो सबको दिख जाएगा। हमारे देश में एफआईआर दर्ज करना बेहद ही मुश्किल काम है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। खासकर अगर वो एफ आईआर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में होगी; विशेषकर किसी जज, राजनेता इत्यादि के बारे में तो यह लोहे के चने चबाने से कम नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसले में कहा है कि यह पुलिस का फर्ज है कि जब भी कोई व्यक्ति एफआईआर लिखवाने आए तो उसे चाहिए कि एफ आईआर दर्ज करे। 2013 में ललिता कुमारी के मामले में भी उसने यह बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा था कि पुलिस को यह प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है कि एफआईआर सही है या गलत है, विश्वसनीय है या नहीं है। अगर कोई राज्य को या पुलिस को किसी अपराध होने की जानकारी दे रहा है तो उसे एफ आईआर दर्ज करना पड़ेगा। कानून समान समझ पर आधारित होता है। इसलिए कानून की नजर में एफ आईआर कोई सबूत नहीं बल्कि सूचना है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून हरकत में आ जाए। इसलिए अच्छी बात है कि राजस्थान सरकार ने इस बिल को अब सलेक्ट कमिटी के पास भेजकर ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कुल मिलाकर भाजपा शासन को इस अध्यादेश को पूरी तरह वापस लेना चाहिए।

चलते चलते

ट्रेन में यात्रा

छठ पर घर जाने के लिए लोगों ने ट्रेनों के शौचालयों में खड़े होकर 20 घंटे से ज्यादा की यात्रा की है। जिन्होंने ऐसे दृश्य नहीं देखें हैं, उन्हें यह अविश्वसनीय लगे। लेकिन जो लोग बिहार से हैं, उनके लिए ऐसे मौकों पर घर पहुंचना किसी मिशन से कम नहीं होता। इस महादिक्कत-महापरेशानी को लेकर हम थोड़े समय के लिए रेलवे को कोस सकते हैं। लेकिन समस्या की जड़ में कहीं-न-कहीं पलायन का मसला भी है। करोड़ों की तादाद में लोग रोजी-रोटी के लिए पलायन करते हैं।

संयोग दुर्लभ ही होता है कि कोई बिहार जाना चाहे और उसे टिकट कन्फर्म मिल जाए। ये तो आम दिनों के हालात हैं। मगर टिकट कन्फर्म होने के बावजूद होली-छठ पर्व पर ट्रेन में यात्रा करने के लिए आपको मजबूत दिल वाला होना होगा।एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक छठ पर घर जाने के लिए लोगों ने ट्रेनों के शौचालयों में खड़े होकर 20 घंटे से ज्यादा की यात्रा की है। जिन्होंने ऐसे दृश्य नहीं देखें हैं, उन्हें यह अविश्वसनीय लगे। लेकिन जो लोग बिहार से हैं, उनके लिए ऐसे मौकों पर घर पहुंचना किसी मिशन से कम नहीं होता। इस महादिक्कत-महापरेशानी को लेकर हम थोड़े समय के लिए रेलवे को कोस सकते हैं। लेकिन समस्या की जड़ में कहीं-न-कहीं पलायन का मसला भी है। करोड़ों की तादाद में लोग रोजी-रोटी के लिए पलायन करते हैं। जाहिर है राज्य की बदहाली से इसका सीधा संबंध है। इसके लिए 90 के दशक में लालू-राबड़ी देवी के शासनकाल को सबसे ज्यादा दागदार माना जाता है। यह वो दौर था जब हिन्दी पट्टी के अधिकतर राज्य खुद को बीमारू राज्यों की सूची से बाहर निकाल ले जाने में सफल रहे। परंतु ''नये बिहार' के नारे के साथ सत्ता में आए नीतीश कुमार दशक भर से ज्यादा सत्तासीन होने के बावजूद पलायन के मोर्चे पर हांफते दिखते हैं। भले ही सड़क-बिजली जैसे मोर्चे पर उनका प्रदर्शन बेहतर रहा हो किंतु कानून-व्यवस्था की बिगड़ी चाल और रोजगार-निवेश की दयनीय दशा अच्छे कामों पर पानी फेर रही है।

हाल के समय में पंजाब में किसानों द्वारा बिहार से आने वाले मजदूरों की किल्लत की बात की थी लेकिन उसकी वजह मनरेगा था न कि सुशासन। वैसे कम आमदनी के लिए पलायन के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि जितना पैसा वो बाहर रहकर बचा लेते हैं, अगर स्थानीय स्तर पर काम करें तो उतना वो यहां भी कमा सकते हैं। यहां तक कि इज्जत के नाम पर बाहर रहकर खुद की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। लेकिन मौजूं सवाल अब भी यही कि विकास के तमाम दावों के बीच पलायन थम क्यों नहीं रहा है?

मुद्दा

''माउंटेन ऑफ पीस'

मौसम की मुश्किलों में फंसकर कई जवान ''शहीद' हो जाएं तो इस कुर्बानी को शहादत का दर्जा भी नहीं मिलता। शायद यह बात सरकार को समझ आ गई है, इसीलिए हाल में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भारत-चीन सीमा पर आईटीबीपी की 50 ऐसी चौकियां बनाने का ऐलान किया है, जिनमें तकनीक की मदद से अंदर का तापमान पूरे साल 20 डिग्री बनाए रखा जाएगा। चीन ही नहीं, पाकिस्तान सीमा पर भी ऐसे कई इलाके हैं, जहां हमारे दर्जनों सैनिकों को तकरीबन हर साल सिर्फ कुदरत के कहर के कारण जान गंवानी पड़ती है। उल्लेखनीय है कि इस साल की शुरु आत में पहले तो 26 जनवरी को गुरेज और सोनमर्ग में 15 सैनिक हिमस्खलन (एवलॉन्च) की चपेट में आ गए थे, फिर 28 जनवरी को माछिल सेक्टर में पांच सैनिक ट्रैक के धंसने से बर्फके नीचे दब जाने से मारे गए थे। यह तकरीबन हर साल का किस्सा है। पिछले साल भी फरवरी में सियाचिन के नॉर्थ ग्लेशियर में एवलॉन्च की चपेट में आकर 19-मद्रास रेजिमेंट के 10 जवानों की मौत हो गई थी। ऐसी हर मौत के बाद पूछा जाता है कि क्या किसी तरह वीर जवानों की ऐसी शहादत टाली नहीं जा सकती है? कोई सवा दशक पहले 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसार के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन का दौरा कर उसे ''माउंटेन ऑफ पीस' में बदलने की इच्छा इसी उद्देश्य से जताई थी, ताकि भविष्य में कभी हमारे सैनिक इसलिए जान न गंवाएं कि वे दुश्मन बन गई कुदरत से लड़ नहीं पाए। गौरतलब है कि वर्ष 1984 से, जबसे सियाचिन पर भारत ने अपना अधिकार किया है, इस इलाके में हमारे 900 से ज्यादा जवानों की मौत की वजह कठिन मौसम रहा, न कि शत्रु पड़ोसी का कोई धावा। भारत, चीन और पाकिस्तान के कब्जे वाले उत्तरी कश्मीर के इस इलाके 22 ग्लेशियर हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 11 हजार 400 से 20 हजार फीट तक है। यहां का औसत तापमान शून्य से 200 डिग्री नीचे तक चला जाता है। यहां इंसान ही नहीं, मशीनें भी अपनी क्षमता का महज एक चौथाई काम कर पाती हैं। मौसम की जटिलताओं के कारण, अच्छे-से-अच्छा भोजन लेने पर भी वहां तैनात सैनिकों का वजन प्रति महीने 5 से 8 किलो घटता रहता है। सत्तर और अस्सी के दशक में कश्मीर के ऊंचे इलाकों समेत सियाचिन में सिर्फ पर्वतारोही ही जाते थे। उस समय पाकिस्तान ने भी काराकोरम और सियाचिन क्षेत्र में देसी-विदेशी पर्वतारोहियों को जाने की इजाजत दे रखी थी। पर 1984 से ये हालात बदल गए हैं। वर्ष 1984 में भारत ने ''ऑपरेशन मेघदूत' नामक अभियान चलाकर सियाचिन के जिस इलाके पर अपना नियंतण्रस्थापित किया था, उसके करीब 2600 वर्ग किलोमीटर हिस्से की निगरानी सैनिकों के जिम्मे आ गई। रणनीतिक रूप से देखें तो भारतीय सेना ने सियाचिन के दो प्रमुख दरे बिलाफेंडला और सियाला को अपने अधिकार में लिया था। इससे पाकिस्तान की सियाचिन और कश्मीर के बर्फीले इलाके में प्रभावी पहुंच की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई थी। कहने को तो 2003 में इस क्षेत्र में दोनों देशों ने युद्धविराम लागू कर दिया था, लेकिन कारगिल घुसपैठ के बाद से दोनों सेनाएं अब वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इस कारण अब तक दोनों मुल्कों के 2 हजार से ज्यादा सैनिक यहां जान गंवा चुके हैं। पर किसी युद्ध में नहीं, बल्कि फ्रॉस्टबाइट की समस्या होने, ऑक्सीजन की कमी, हिमस्खलन में दब जाने और दूसरे प्राकृतिक कारणों से।

जंग के बिना ही जिस इलाके में सैनिक अपनी जान गंवाते रहे हैं। साफ है कि ऐसे इलाके में कुदरत सबसे बड़ी दुश्मन है। उन्हें वातानुकूलित चौकियां, शरीर को गर्म रखने वाले आधुनिक उपकरण के साथ-साथ पड़ोसी मुल्क की भाषा से भी लैस किया जाए ताकि उनकी सैन्य हलचलों पर बारीक नजर रखी जा सके। चीनी सरहद पर तैनात सैनिकों को मंडारिन (चीन की भाषा) सिखाने का मकसद यही है, इसी तरह पश्तो आदि भाषाएं भी उन्हें सिखाई जाएं।

अर्थव्यवस्था को संजीवनी का मंत्र

आभा स्वामी

सरकार की पुरजोर कोशिश है कि भारत वैश्विक विनिर्माण का गढ़ बन जाए। इसके लिए 'मेक इन इंडिया के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में फैक्ट्रियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि रोजगार के अवसर सृजित हों और लोगों की आमदनी बढ़े। इस दिशा में सरकार ने दो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला कदम वित्तीय घाटे पर नियंत्रण का है। सरकार द्वारा आय से अधिक खर्च करने के लिए जो ऋण लिया जाता है, उसे वित्तीय घाटा कहते हैं। सरकार का वित्तीय घाटा उसी प्रकार है, जैसे उद्यमी द्वारा बैंक से लोन लेकर आय से अधिक खर्च किया जाता है। वर्ष 2013-14 में वित्तीय घाटा देश की आय का 4.5 प्रतिशत था, जो बीते वर्ष 2016-17 में 3.5 प्रतिशत रह गया और चालू वित्त वर्ष 2017-18 में 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्तीय घाटा कम होने से सरकार द्वारा पूर्व में जो कर्ज लेकर भारी खर्च किए जा रहे थे, उनमें कटौती करनी होगी। यूं समझें कि सरकार द्वारा पूर्व में अर्थव्यवस्था को वित्तीय घाटे का जो टॉनिक दिया जा रहा था, उसकी मात्रा कम करनी होगी। वित्तीय घाटे पर नियंत्रण का उद्देश्य है कि वैश्विक निवेशकों का हमारी अर्थव्यवस्था पर भरोसा बने और वे यहां व्यापक निवेश करें। विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की दृढ़ मान्यता है कि वित्तीय घाटे पर नियंत्रण से अर्थव्यवस्था में स्थिरता आती है व विदेशी निवेश आकर्षित होता है। सरकार ने दूसरा महत्वपूर्ण कदम बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने का उठाया है। बुलेट ट्रेन, राष्ट्रीय राजमार्ग, एयरपोर्ट एवं राष्ट्रीय जलमार्गों पर भारी निवेश किया जा रहा है। रातोंरात नए हाईवे बन रहे हैं। निवेश में वृद्धि विशेष तौर पर उल्लेखनीय है, क्योंकि इसके साथ ही वित्तीय घाटे पर काबू किया जा रहा है। यानी कुल खर्चों पर दबाव है, जबकि बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ रहा है। इस निवेश के पीछे भी विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने का लक्ष्य है। इनकी मांग रही है कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में उनके लिए भारत में फैक्ट्रियां लगाना कठिन है। सरकार के इन अथक प्रयासों का सुखद परिणाम भी आने के संकेत मिल रहे हैं। मोबाइल कंपनी जियोनी और एप्पल, फर्नीचर कंपनी आइकिया एवं इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने भारत में फैक्ट्रियां लगाने के संकेत दिए हैं।

चिंता का विषय यह है कि सरकार द्वारा उठाए गए इन साहसिक एवं प्रभावी कदमों के बावजूद आर्थिक विकास दर बढ़ नहीं रही है। इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें अलग-अलग प्रकार की बुनियादी संरचना के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को देखना होगा। वित्तीय घाटे पर नियंत्रण ने समस्या को और विकराल बना दिया है। ऊपर बताया गया कि सरकार द्वारा वित्तीय घाटा कम किया जा रहा है, लेकिन बुनियादी ढांचे में भी खर्च बढ़ाया जा रहा है। जाहिर है कि किसी अन्य मद में कटौती की जा रही है। मैं ऐसी कटौती का समर्थन करता हूं,ऋण लेकर निवेश करने अथवा वित्तीय घाटे को बढ़ाने का दुष्प्रभाव नहीं होगा, बल्कि वित्तीय घाटे को बढ़ाकर निवेश करने से घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और विदेशी निवेश ज्यादा आएगा। वहीं, सरकार को बुनियादी ढांचे में निवेश के मोर्चे पर संतुलन बनाना होगा। केवल हाईवे बनाने से अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी, जैसे केवल नहर बनाने से बात नहीं बनती है, फीडर भी बनानी होती है। सरकार वित्तीय घाटे को बढ़ाकर बुनियादी संरचना में संतुलित निवेश करे तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है।

यूपी में ई-आफिस सिस्टम शुरू, योगी बोले- तय होगी जवाबदेही

लखनऊ। मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव कार्यालय सहित सचिवालय के 22 विभागों में शुक्रवार से ई-आफिस व्यवस्था लागू हो गई। अब इन विभागों की सभी फाइलें कंप्यूटर पर तैयार होंगी और ऑनलाइन दौड़ेंगी। उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा कि ई-आफिस शुरू होने का यह दिन ऐतिहासिक है। इस सिस्टम से जनता के प्रति जवाबदेही तय होगी। ई-आफिस से पर्यावरण की रक्षा भी होगी। सचिवालय स्थित तिलक हॉल में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सिस्टम का लाभ राज्य की 22 करोड़ जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सचिवालय के शेष 72 विभागों में 31 दिसंबर तक और सभी जिला मुख्यालयों में 31 मार्च तक ई-आफिस से कामकाज शुरू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा भी यही है कि सरकार के कामों में पारदर्शिता हो। इससे काम में पारदर्शिता के साथ ही समयबद्धता भी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा।

सचिवालय की फाइलों की भीड़ में दमा हो जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने एक बार सचिवालय का निरीक्षण किया। जिसमें फाइलों की भीड़ देख ऐसा लगा कि यहां बैठने वालों को दमा हो जाए। ई-आफिस से कार्यालयों में फाइलों का दबाव कम होगा। कागज की खपत भी कम होगी, जो पर्यावरण के लिहाज से बेहतर है। बताया कि 12,500 पेपर के लिए एक बड़ा पेड़ काटना पड़ता है। फाइल सिस्टम से नौकरशाही व्यवस्था कटघरे में रहती है, इससे भी छुटकारा मिलेगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डॉ. दिनेश शर्मा, मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना और मुख्य सचिव राजीव कुमार आदि भी उपस्थित थे। स्वागत सचिवालय प्रमुख सचिव महेश गुप्ता ने किया।

इन विभागों में शुरू हुआ ई-आफिस सिस्टम से काम

मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यात प्रोत्साहन विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, दुग्ध विकास विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, लघु सिंचाई विभाग, होमगार्ड विभाग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग, संस्कृति विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, आबकारी विभाग, सूचना विभाग, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, निर्वाचन विभाग, मत्स्य विभाग, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, खेलकूद विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, युवा कल्याण तथा पर्यावरण विभाग में शुक्रवार से ई-आफिस सिस्टम से ऑनलाइन कामकाज शुरू हुआ।

दुधवा में जल्द आबाद होगा गैंडों का नया आशियाना

लखीमपुर-खीरी। यूपी के इकलौते नेशनल पार्क दुधवा के बेलरायां रेंज में अरसे से तैयार नया राइनो एरिया जल्द ही आबाद हो जाएगा। गैंडों को नए आशियाने में शिफ्ट करने को बेहोशी की जिस दवा का इंतजार था, उसे दक्षिण अफ्रीका से मंगवाने का रास्ता साफ हो गया है। दुधवा के सोनारीपुर रेंज में 27 वर्ग किमी के परिक्षेत्र में तीन दशक पहले अप्रैल गैंडा पुनर्वास परियोजना की शुरुआत हुई थी। यह तराई की धरती से विलुप्त हो चुके गैंडों को करीब डेढ़ सदी बाद फिर से आबाद करने का अनूठा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। महज पांच गैंडों के साथ शुरू हुए इस पुनर्वास में गैंडों को दुधवा की आबोहवा इस कदर रास आई कि उनका कुनबा आज तीन दर्जन के आसपास हो चुका है। गैंडों का बढ़ते कुनबे ने कुछ चिंताएं भी बढ़ा दीं। 27 वर्ग किमी के बाड़े में तीन दर्जन गैंडों की मौजूदगी उनके बीच संघर्ष का कारण बन रही थी। संघर्ष में कुछ गैंडे पार्क से निकल भागे तो कुछ को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक और चिंता जेनेटिक प्रदूषण की थी। अब बेलरायां रेंज में 27 वर्ग किमी में बने गैंडों का नया आशियाना भी तैयार हो चुका है। दुधवा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर महावीर कौजलगि बताते हैं कि गैंडों को अचेत कर नए राइनो एरिया में ले जाया जाना है। इसके लिए इटॉर्फिन एम 99 नाम की दवा की जरूरत थी।

यह दवा भारत में नहीं बनती। इसे दक्षिण अफ्रीका से मंगवाना था। आयात के लिए जरूरी औपचारिकताओं के पूरा न होने से यह लटका हुआ था। अब भारतीय औषधि नियंत्रक, केंद्रीय पशुपालन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों से अनुमति पत्र मिल चुका है।

कौजलगि के अनुसार जिला प्रशासन ने भी इटॉर्फिन के लिए एनओसी जारी कर दी है।

पुरातत्व विभाग का नोटिस: खाली करो सहारनपुर जेल, राष्ट्रीय धरोहर

नई दिल्ली। पुरातत्व विभाग ने सहारनपुर जिला कारागार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते हुए उसे खाली करने और इमारत में किसी तरह का कोई बदलाव किये जाने पर भी रोक लगा दी है।सहारनपुर जिला कारागार को 147 साल पहले वर्ष 187० में अंग्रेजों ने जिला जेल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। पुरातत्व विभाग की जांच में यह बात सामने आई है कि रोहिला वंश के समय में यह इमारत राजा का महल हुआ करता था।

सहारनपुर कारागार के अधीक्षक वीरेश राज शमार ने आज यहां बताया कि कार्यवाहक अपर पुलिस महानिरीक्षक (जेल) शशि श्रीवास्तव ने इस कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस कारागार की क्षमता 53० बंदियों की है, लेकिन उसमें 1690 बंदी रह रहे है। महिलाओं और बालकिशोर की जेल भी इसी रोहिला महल का हिस्सा है।

सं भंडारी

आयुक्त दीपक अग्रवाल ने प्रदेश के गृह विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि सहारनपुर में अब नई जेल के निमार्ण किए जाने की जरूरत है। इसके लिए शासन की ओर से जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए जिससे आधुनिक सुविधाओं से संपन्न जेल का निमार्ण संभव हो सकेगा। डीआईजी जेल शशि श्रीवास्तव के मुताबिक वर्तमान कारागार में शौचालयों का अभाव है। इसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग और पीसीओ की भी व्यवस्था के लिए भवन नहीं है।

पुरातत्व विभाग ने इस भवन को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने संबंधी शिलालेख भी लगा दिया है। सहारनपुर के इतिहास के जानकारों का कहना है कि ब्रिटिशकाल के दौरान सहारनपुर रोहिला वंश के राज्य के अधीन आता था और जो अब जिला कारागार है। यह रोहिला वंश के दौरान राजा का महल हुआ करता था। इसे सन 1870 से जिला जेल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना पुराना भवन होने के कारण इसमें बनी कई बैरकों की दीवारें जीर्णक्षीण हालत में है और कारागार अधिकारियों के भवन का भी खस्ता हाल है। पुरातत्व विभाग की नये निमार्ण या मरम्मत पर रोक के कारण जीवन का जोखिम उठाकर यहां कैदियों को रखा जा रहा है।

श्री अग्रवाल ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है। शासन की ओर से इस संबंध में अभी कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जेल भवन को किसी भी दृष्टि से मौजूदा हालत में सुरक्षति नहीं माना जा सकता है। सहारनपुर में नया जेल बनने में कम से कम पांच से सात वर्ष का समय लग सकता है। ऐसे हालात में पुरातत्व विभाग के निदेशों के मुताबिक इस भवन को संरक्षति रखना बेहद कठिन है।

गन्ना ढुलाई दर में कटौती से किसानों को होगी अतिरिक्त आमदनी : सुरेश राणा

लखनऊ। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुरुवार की रात घोषित गन्ना मूल्य के साथ इस बार के पेराई सत्र के लिए गन्ने की ढुलाई दर में जो कटौती की गयी है, उससे किसानों को 1060 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। गन्ना मूल्य अपेक्षा के अनुरूप न बढ़ाए जाने पर किसान संगठनों की नाराजगी पर प्रतिक्रिया जताते हुए उन्होंने कहा कि इस बार गन्ने के राज्य परामर्शी मूल्य में वैसे तो दस रुपए प्रति कुन्तल की बढ़ोतरी की गयी है मगर ढुलाई दर की व्यवस्था में बदलाव से गन्ना किसान को दस से पन्द्रह रूपए प्रति कुन्तल का और लाभ होगा। इस तरह से किसान को प्रति कुन्तल गन्ने की आपूर्ति पर लगभग 25 रुपए इस बार बढ़कर मिलेंगे। शुक्रवार को यहां गन्ना किसान संस्थान के सभाकक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में श्री राणा ने कहा कि इस बार किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलें एक किस्त में करेंगी। किसान को गन्ना आपूर्ति के चौदह दिन के भीतर उसके पूरे गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

ढुलाई दर की पुरानी व्यवस्था बदले जाने से चीनी उद्योग की नाराजगी के बाबत श्री राणा ने कहा कि पेराई सत्र 2017-18 के लिए चीनी मिलों को वाहय क्रय केन्द्र से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराए जाने में होने वाली ढुलाई कटौती की दर केन्द्र सरकार की 27 सितम्बर 2017 की अधिसूचना के अनुसार 42 पैसे प्रति कुन्तल प्रति किलोमीटर अधिकतम 08 रुपए 35 पैसे प्रति कुन्तल निर्धारित की गयी है।

यूपी के इस शहर में किन्नरों ने अनाथ बच्चों के लिए रखा छठ व्रत

गोरखपुर। पूरे देश में छठ का पर्व पूरे देश धूमधाम से मनाया गया। आज लोगों ने उगते हुए सूर्य अर्घय देकर अपना व्रत पूरा किया।

छठ के इस पावन पर्व पर उत्तरप्रदेश के गोरखपुर की किन्नरों ने अनाथ बच्चों के लिए छठ व्रत रखा। शुक्रवार को भोर में उगते सूर्य को अर्घय देकर व्रत पूरा किया। किन्नर शोभा, प्रेमा, सरस्वती, छोटकी ने जंगल मातादीन में तालाब किनारे बने घाट पर छठ माता की मूर्ति भी स्थापित कराई।

उत्तर प्रदेश:स्विस जोड़े पर हमले के मामले में योगी गंभीर, अब तक 5 गिरफ्तार

आगरा। फतेहपुर सीकरी में 22 अक्टूबर को स्विटजरलैंड के युगल पर हमले के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस मामले में गुरुवार तक पांच हमलावर गिरफ्तार भी कर लिए गए। गिरफ्तार आरोपियों का कहना है कि उन्होंने सनक में पत्थर मार दिए थे। स्मारक से करीब दो किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के पास वारदात हुई थी। पहले दिन पुलिस ने यह कहकर मामले को हल्का कर दिया था कि विदेशी पर्यटक कोई कार्रवाई नहीं चाहते। गुरुवार को मुख्यमंत्री के आगरा दौरे के दौरान यह मामला सुर्खियों में आ गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने योगी सरकार से रिपोर्ट मांगी। खुद मुख्यमंत्री ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए। शाम तक पांच आरोपी मुकुल, राहुल, पंकज, सनी और हनीफ पकड़ भी लिए गए। एसपी देहात पश्चिम अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि जांच में पता चला कि घटना में कुल पांच लड़के शामिल थे। विदेशी युगल को पत्थर और डंडे से मारा गया था। गिरफ्तार आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है।

स्विस युगल के स्वास्थ्य में सुधार

फतेहपुर सीकरी में रविवार को बदमाशों के हमले का शिकार हुए युवा स्विस युगल की सेहत में सुधार हो रहा है। अपोलो अस्पताल में भर्ती युगल का उपचार कर रहे न्यूरोसर्जन डॉक्चर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जेरेमी क्लेर्क को आईसीयू से सामान्य कक्ष में भेज दिया गया है। वहीं उसकी महिला मित्र मैरी द्रोज की बांह की हड्डी टूट गई है। उपचार के बाद उन्हें भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। प्रसाद ने कहा, क्लेर्क को अभी सुनने में दिक्कत आ रही है। इस वक्त यह कहना मुश्किल है कि उनके सुनने की समस्या स्थायी बनी रहेगी या ठीक हो सकती है। घटना के बाद दोनों सदमे में हैं। स्विटजरलैंड के लुसाने के रहने वाले इस युगल पर रविवार 22 अक्तूबर को फतेहपुर सीकरी में कुछ युवकों ने पीछा कर पत्थरों एवं लाठियों से हमला किया था। रिपोर्ट के अनुसार जब वे जमीन पर घायल पड़े थे तब वहां खड़े लोग अपने मोबाइल फोन से उनका वीडियो बना रहे थे।

विदेशी युवती के मोबाइल में कैद थे हमलावर

स्विस पर्यटकों पर पथराव करने वालों की पहचान में विदेशी युवती का मोबाइल फोन मददगारर बना। हमलावरों के फोटो विदेशी युवती के मोबाइल में कैद मिल गए। उन्होंने पुलिस की राह आसान कर दी। एसपी देहात पश्चिम अखिलेश नारायण ने बताया कि 23 अक्तूबर को एक दरोगा को दिल्ली भेजा गया था। वहां हॉस्पिटल में दरोगा ने जख्मी विदेशी युगल से बातचीत की। युवती के मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ थे। उन्हीं के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई।

बिहार

छठ महापर्व: राबड़ी देवी-लालू यादव ने घर पर ही दिया सूर्य को अर्घय

पटना। उदीयमान सूर्य को अर्घय देने के साथ ही महापर्व छठ संपन्न हो गया। पूरे बिहार में छठ पर्व का उल्लास रहा। छठ व्रतियों ने बड़ी निष्ठा के साथ उगते सूर्य को अर्घय दिया। सूयीदय का समय 6.28 बजे था, लेकिन इससे पहले ही आकाश में लालिमा छाते ही व्रतियों ने सूर्य को अर्घय देना शुरू कर दिया।

हालांकि कोहरा होने के कारण सूर्य देवता थोड़े देर से निकले। व्रतियों ने सूर्य की उपासना के बाद घाट पर लोगों को प्रसाद वितरित किये। व्रतियों ने भी पारण किया। पटना के गंगा घाटों पर उगते सूर्य को अर्घय देने के लिए लाखों की श्रद्धालुओं की भीड़ जमा थी। कलेक्ट्रेट घाट, गांधी घाट, काली घाट, कदम घाट, वंशी घाट महेन्द्रू, दीघा पाटी पल घाट, दीघा पिलर 93 आदि घाटों पर सुबह 3 बजे ही लोग पहुँच गए। घाटों पर सायंकालीन अर्घय के मुकाबले सुबह में अधिक भीड़ थी।

लालू के आवास पर अर्घय

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के घर पर छठ की चहल पहल रही। राबड़ी देवी ने उदीयमान सूर्य को अर्घय दिया। इस अवसर पर लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद, तेजप्रताप, मीसा भारती समेत अन्य लोगो ने सूर्य को अर्घय दिया। अर्घय देने के बाद सबको प्रसाद बाटें गए।

मुख्यमंत्री के यहां भी छठ की रही धूम : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर छठ का भक्तिमय माहौल रहा। मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार ने उदीयमान सूर्य को अर्घय दिया। मुख्यमंत्री की भाभी, भतीजी, भांजे की पत्नी और भांजी छठ कर रही हैं। गया में जापानी पर्यटकों ने दिया अर्घय : गया में निरंजना नदी के बकरौर घाट पर जापानी पर्यटकों ने अर्घय दिया। विदेशी सैलानियों में छठ का उत्साह देखते बन रहा था। वही गया के फल्गु नदी के तट पर हजारों लोगों ने उदीयमान सूर्य को अर्घय दिया।

देव में 6 लाख लोगों ने दिया अर्घय : इधर औरंगाबाद के देव में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घय दिया। रात दो बजे से श्रदालु मंदिर पहुँचने लगे।

रामकृपाल ने पुनपुन में दिया अर्घय : केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने पुनपुन नदी के तट पर गौरीचक पुल के नीचे प्लांकी घाट पर अर्घय दिया।

बाढ़ में महापर्व छठ का समापन : उदयाचल भगवान भास्कर को अर्घय देने के साथ संपन्न हो गया । बाढ़ नगर के उमानाथ, अलखनाथ तथा सीढ़ी गंगा घाटों पर करीब डेढ़ लाख लोगों ने पहुंचकर भगवान सूर्य देव की आराधना की ।

प्लास्टिक मल्च के प्रयोग से सब्जी की खेती में अधिक होगी आमदनी : डॉ. प्रेम

पटना.सब्जी की खेती के लिए प्लास्टिक मल्च के प्रयोग से कम पानी में अधिक ऊपज मिलेगी। इससे आमदनी भी अधिक होगी। कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि 2017-18 में राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन व मुख्यमंत्री बागवानी मिशन से तीन हजार हेक्टेयर खेतों में प्लास्टिक मल्च की योजना स्वीकृत की गई है। इकाई लागत 32 हजार रुपए है, इसमें 50 प्रतिशत यानी 16 हजार प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है। प्लास्टिक मल्च तकनीक से खेती करने के लिए सब्जी खेत में एक मीटर चौड़ी बेड का निर्माण कराना होता है। बेड के बीच 60 सेंटीमीटर का जगह रखना है, जो सब्जी के खेत में सब्जी उत्पादकों को देखभाल करने के लिए जगह के साथ-साथ सिंचाई नाला का कार्य करेगा। इस प्रकार से तैयार खेत में बनाए गए सब्जी बेड पर प्लास्टिक शीट बिछाकर दूरी के अनुसार बिछाए गए प्लास्टिक में 15-20 सेंटीमीटर गोलाकार कट कर दिया जाता है।

राज्य में लगभग 826.853 हजार हेक्टेयर रकवा में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती की जा रही है। सब्जी की खेती में अत्यधिक मानव बल लगता है तथा खरपतवार एवं कीट-व्याधि का प्रकोप भी अधिक होता है, जिसके नियंत्रण हेतु काफी खर्च उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सब्जी के खेती में सिंचाई जल की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। प्लास्टिक मल्च का उपयोग कर इन समस्याओं से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है एवं खेती की लागत व्यय को भी कम किया जा सकता है। प्लास्टिक मल्च का उपयोग करने से खेत में जो भी खरपतवार उगते हैं वो प्लास्टिक से दबकर नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार खाद के रूप में तब्दील हो जाते हैं। खर-पतवार के नष्ट होने के फलस्वरूप जमीन के पोषक तत्व के बचाव के साथ-साथ कीट-व्याध के प्रकोप भी कम हो जाते हैं।

छठ मनाने हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन, कहा- यहां बिहार जैसा माहौल

हरिद्वार। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने हरकी पैड़ी पर छठ महापर्व के अवसर पर बोलते हुए कहा कि छठ वास्तव में प्रकृति की पूजा है। छठ का पौराणिक महत्व तो है ही बल्कि पूरी वैज्ञानिक आधार भी है। बताया कि दुनिया आज जिस आधुनिक विज्ञान की बातें करती है वास्तव में वह हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों की देन है। उन्होंने कहा कि यहां घर जैसा माहौल है। बिहार निवासी केंद्रीय मंत्री के गृहजनपद मोतिहारी के भूपेश कुमार सिंह का परिवार भी हरकी पैड़ी पर छठ पूजन के लिए पंहुचा था। केंद्रीय मंत्री जब उनसे मुलाकात करके आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि यहां बिल्कुल अपने घर जैसा ही लग रहा है। मंत्री ने कहा कि पूर्वांचल ही नहीं पूरा देश यहां दिखाई दे रहा है। छठ पूजन करने आए परिवारों से गंगाजी हरकी पैड़ी गुरुवार की शाम पूरी तरह खचाखच भरी रही। केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह के लिए भाजापाईयों ने एक मंच तैयार किया था लेकिन मंच पर बैठने से पहले उन्होंने जगह जगह बैठकर छठ पूजन की तैयारी कर रहे लोगों से जाकर मुलाकात की और हालचाल पूछने के बाद छठ की बधाई दी। मुलाकात के उन्होंने मंच पर बैठकर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छठ वास्तव में प्रकृति का पूजन होता है। इस अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, मेयर मनोज गर्ग, सुशील चौहान, नरेश शर्मा, विकास तिवारी, आशीष चौधरी, मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपडा, कामिनी सडाना, सरोज जाखड, ललिता मिश्रा, राकेश उपाध्याय, संजय शांडिल्य, पुरोषोत्तम शर्मा, विजय कुमार शास्त्री, पंकज शांडिल्य और भजन मंडली के सनोज बंशी, आशीष बजाज, राखी, सोनू, शशि गौतम मुख्य रुप से उपस्थित रहे।

छठ मेला में करने वाले थे आपराधिक वारदात, पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार

सहरसा.सहरसा जिले के महिषी प्रखंड में स्थित कन्दाहा सूर्य मंदिर के निकट छठ पर्व पर लगने वाले मेला में आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से योजना बनाने वाले नशे में चूर पांच अपराधी पुलिस के हथ्थे चढ़ गए। पुलिस की गिरफ्त में आने वालों में महिषी प्रखंड के पस्तपार पंचायत के मुखिया राहुल राज भी शामिल है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से बम बनाने वाले विस्फोटक पदार्थ के साथ 3500 रुपए, 6 मोबाइल, एक सफारी गाड़ी तथा एक मोटर साइकिल भी जप्त कर लिया है। सहरसा के एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने गुरुवार को बताया की बुधवार की रात सदर थाना क्षेत्र अन्तर्गत कहरा कुटी स्थित जोड़ी पोखर के निकट महिषी की तरफ से आ रही सफारी गाड़ी को सदर थाना की गश्ती पुलिस ने रोका। गाड़ी नहीं रुकी। बाद में गश्ती पुलिस ने इसकी सूचना सदर थाना अध्यक्ष को दी और सदर थाना अध्यक्ष ने इसकी सूचना उन्हें दी। सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई कर उस सफारी गाड़ी को पकड़ कर तलाशी ली लगी। तलाशी के दौरान वाहन में रखे विस्फोटक पदार्थ को देख सभी हैरान रह गए। उसे जप्त कर लिया गया। वाहन में बैठे सभी पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। नशे की हालत में गिरफ्तार किए गए मुखिया सहित अन्य सभी अपराधी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। कन्दाहा सूर्य मंदिर के निकट लगने वाले मेला में आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना थी।

हादसा:सीतामढ़ी में गैस रिसाव से 1 ही परिवार के 8 बच्चों समेत 11 झुलसे

सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिला के परिहार थाना के महादेव पट्टी गांव में बुधवार की रात एलपीजी गैस रिसाव से एक ही परिवार के 8 बच्चों सहित 11 लोग झुलस गए। सब को सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। सभी की हालत गंभीर है।

घायलों में मुकेश पासवान-42, दीपक कुमार-दो.वर्ष, सन्नी कुमार-2, विजय कुमार-7, माशूम कुमार-10, आशिकी कुमारी-दो माह, नीतू कुमारी-6, रिम्पी कुमारी-8, शिम्पी कुमारी-2, राधा कुमारी-6, राम प्रवेश पटेल-30 शामिल है। घटना के संबंध में मुकेश पासवान

छठ घाट पर दो बच्चों की हत्या कर तालाब में फेंका

गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज थाने के विश्रामपुर गांव के समीप स्थित पोखरे के किनारे बने छठ के प्रतीक चिन्ह की रंगाई करने गए दो बच्चों की हत्या कर पोखरे में फेंक दिया गया। बुधवार देर शाम को दोनों बच्चों के शव पोखरे से बरामद किया गया। मृत बच्चों में विश्रामपुर कुम्भी टोला गांव के अवधेश पाण्डे का नौ वर्षीय पुत्र सुमित और उसका फुफेरा भाई यूपी के कुशीनगर जिले के भेलेया चंद्रवटा गांव के ओमप्रकाश मणि त्रिपाठी का दस वर्षीय पुत्र विनीत कुमार शामिल हैं।

बताया जाता है कि विनीत अपनी मां के साथ छठ मनाने मामा के घर आया हुआ था। बुधवार की दोपहर बाद दोनों बच्चे छठ का प्रतीक चिन्ह श्री सोप्ता की रंगाई करने गए थे। शाम तक जब दोनों बच्चे लौटकर नहीं आए तब परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी।मृत बच्चों में विश्रामपुर कुम्भी टोला गांव के अवधेश पाण्डे का नौ वर्षीय पुत्र सुमित और उसका फुफेरा भाई यूपी के कुशीनगर जिले के भेलेया चंद्रवटा गांव के ओमप्रकाश मणि त्रिपाठी का दस वर्षीय पुत्र विनीत कुमार शामिल हैं।

बाद में देर शाम को पोखरे से दोनों बच्चों का शव बरामद किया गया। शव को देखने पर पता चला कि सुमित का एक हाथ तथा विनीत का एक पैर टूटा हुआ था।वही सुमित का सर भी पीछे कटा था,जिससे खून निकला था। बच्चों के कपड़े घाट के किनारे से बरामद किए गए। कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे।

भाजपा दफ्तर में कार्यकर्ताओं की सुनेंगे मंत्रीजी, हर सप्ताह एक दिन देना होगा समय

पटना.भाजपा के प्रदेश दफ्तर में मंत्रियों का कार्यकर्ता दरबार लगेगा। इसमें वे पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे और उसका निदान करेंगे। नवंबर से यह कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें भाजपा कोटे के सभी मंत्री पार्टी के प्रदेश दफ्तर में निश्चित दिनों को आएंगे और वहां कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। पार्टी मंत्रियों के दिन और समय को अंतिम रूप देने में जुटी है। पार्टी यह अहसास कराना चाहती है कि सूबे में उनकी सरकार है और वह काम कर रही है। पिछले दिनों दिल्ली में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश इकाई को यह टास्क सौंपा था। उनसे दो टूक कहा गया था कि मंत्रियों को एयरकंडीशन रूम से बाहर आकर काम करना होगा। यही नहीं, उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी न केवल सुनना होगा बल्कि उसके निदान के लिए गंभीरता से प्रयास भी करने होंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि किसी स्तर पर कार्यकर्ताओं की बात अनसुनी नहीं रहनी चाहिए।

पार्टी ने कार्यकर्ता दरबार में उनकी बात तो सुनेंगे ही, उनके माध्यम से आम लोगों की समस्याओं को भी मंत्रियों के सामने रखेंगे। इसके निराकरण के लिए भी पहल होगी। वर्ष 2005 में सूबे में एनडीए की सरकार बनने के बाद भाजपा मंत्रियों को कार्यकर्ताओं की बात सुनने की जिम्मेवारी दी गई थी। उस समय जदयू के मंत्री भी जदयू दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनते थे। बाद में परिस्थितिवश यह बंद हो गया। एनडीए की सरकार बनने के बाद पार्टी के स्तर पर फिर से कार्यकर्ता दरबार आयोजित करने का निर्णय लिया।

सूरत। जलाराम बापा जयंती के उपलक्ष्य में वराछा के लाभेश्वर स्थित जलाराम मंदिर से शुक्रवार को जलाराम बापा की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा लाभेश्वर मंगिर से निकल कर वराछा के मिनी बाजार , सौराष्ट्र पटेल की वाड़ी होते हुए लाभेश्वर मंदिर पहुंच कर सम्पन्न हुई। इस अवसर पर अन्नकूट तथा महाआरती का आयोजन किया गया। कार्तिक शुक्ल सप्तमी पर शुक्रवार को जलाराम बापा की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भागल चौराहे के निकट बालाजी रोड सहित अन्य क्षेत्रों में बापा के मंदिरों में विशेष सजावट की गई, साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया। शहर के भागल, रांदेर रोड, कतारगाम, वराछा सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रही। इस अवसर पर यज्ञ, हवन, पूजन, अनुष्ठान, सत्यनारायण कथा सहित विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए।

हास्पिटल की आया ने डाक्टर पर लगाया यौन शोषण का आरोप

सूरत। डिंडोली क्षेत्र के एक निजी प्रसूति गृह में काम करने वाली महिला ने डाक्टर पर यौन पीड़ा का आरोप लगाते हुए डिंडोली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।

प्राप्त जानकारी अनुसार नवागाम डिंडोली , उमियानगर -1 स्थित श्री सांई हास्पीटल एवं प्रसूति गृह में रहकर बतौर आया का काम करने वाली दलित महिला ने आरोप लगाया है कि डाक्टर विरेंद्र पटेल ने 21 नवंबर 2016 को उसके साथ शारीरिक संभंध बनाया तथा उसकी विडियो क्लीप बना ली। उसके बाद से विडयो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर मार्च 2017 तक उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। पुलिस ने महिला के शिकायत के आधार पर जांच शुरु कर दी है। श्री सांई हास्पीटल एवं प्रसूति गृह में रहकर बतौर आया का काम करने वाली दलित महिला ने आरोप लगाया है कि डाक्टर विरेंद्र पटेल ने 21 नवंबर 2016 को उसके साथ शारीरिक संभंध बनाया तथा उसकी विडियो क्लीप बना ली।

उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ साथ सम्पन्न हुआ चार दिवसीय छठ महापर्व

सूरत। शुक्रवार को कार्तिक शुक्ल सप्तमी पर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सम्पन्न हुआ चार दिवसीय छठ महा पर्व। आस्था के इस महापर्व पर पूरा शहर छठ मईया की भक्ति में रंगा नजर आया। चारों तरफ छठ व्रतियों तथा श्रद्धालुओं की भीड़ से चार दिनों तक पूरा शहर पटा नजर आया। चारों तरफ छठ की लोक गीतों की गूंज सुनाई दी। बिहार, झारखंड, तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रवासी ने अपनी लोक परंपरा के अनुसार छठ मईया की श्रद्धा एवं भक्ति के माहौल में पूजा की।

नहाय खाय के साथ मंगलवार से शुरू हुआ छठ महाव्रत का पारअण शुक्रवार को व्रतियों ने अगते सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात किया। शुक्रवार की तड़के सुबह ही व्रती घाटों पर पहुंचकर सूर्योदय तक छठ मईया की विविध प्रकार से पूजा अर्चना करते रहे। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग- अलग समितियों की तरफ से छठ पूजा का आयोजन किया गया था। शहर के जहांगीरपुरा स्थित इस्कान मंगिर के पीछे तापी नदी के तट पर बिहार विकास परिषद की तरफ से आयोजन किया गया था। वीयर कम कोजवे पर छठ पूजा का आयोजन बिहार विकास मंडल की ओर से किया गया। डाभोली तापी घाट पर छठ पूजा गका आयोजन भी विहार विकास परिषद की तरफ से किया गया था। समस्त बिहार झारखंड समाज की तरफ से पार्ले प्वाइंट के निकट राधा कृष्ण मंदिर के पीछे तापी नदी के तट पर छठ पूजा का आयोजन किया गया। करडवा तालाब पर सार्वजनिक दुर्गापूजा समिति, भेस्तान तालाब पर छठ पूजा सेवा समिति, पालमपोर गांव, जलाराम मंदिर मीनी वीरपुर के समीप नहर पर दिव्य ज्योति सेवा मंडल की तरफ से छठ पूजा का आयोजन किया गया।

सोमोलाई हनुमान गौशाला में आज मनेगा गोपाष्टमी का महापर्व

सूरत। श्री सोमोलाई हनुमान गौ सेवा समिति की ओर से गोपाष्टमी के अवसर पर 28 अक्टूबर, शनिवार को विशाल भजन, गौ पूजन, गौ ग्रास द्वारा गौमाता की पूजा की जाएगी। श्री लक्ष्मीनाथजी परिवार की तरफ विसाल भजन, गौ पूजन, गौ ग्रास, लापसी का भोग गौमाता को लगाया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए गौ सेवा समिति के प्रमुख अरूण पाटोदिया ने बताया कि गोपाष्टमी पर गौ सेवा का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन गौ भक्तों से विशेष निवेदन है कि गौमाता की सेवा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।

सूरत को मिला बेस्ट सिटी बस सर्विस का खिताब

सूरत। सूरत महानगर पालिका द्वारा सार्वजनिक परिवहन सेवा के तहत शहरी जनों को दी जाने वाली बीआरटीएस तथा सिटी बस सेवा के लिए मनिस्ट्री आफ हाउसिंग एण्ड अर्बन अफेयर्स की ओर से सूरत के बेस्ट सिटी बस सर्विस का अवार्ड मिला है। सूरत महानगर पालिका द्वारा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के तहत 25 नवबंर 2016 को शहरीजनों के लिए सिटी बस की सुविधा शुरू की गई थी। एक वर्ष से भी कम समय में सूरत महानगर पालिका द्वारा शहर के अलग अलग 27 रूटों पर 275 सिटी बसें संचालित हैं। जिसमें प्रत्येक दिन 75,000 से अधिक यात्री मुसाफिरी करते हैं। भारत सरकार के मनिस्ट्री आफ हाउसिंग एण्ड अर्बन अफेयर्स नई दिल्ली द्वारा पब्लिक ट्रंसपोर्टेशन के विविध कटेगरी में अवार्ड प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र मगाई गई थी। जिसमें देश भर के सभी महानगर पालिकाओं की तरफ से दावे पेश किए गए थे। उन सभी महानगर पालिकाओं में से सूरत को बेस्ट सिटी बस सर्विस के लिए चुना गया है। जिसके लिए 3 अक्टूबर 2017 को सूरत महानगर पालिका की तरफ से एम नागराजन डेप्युटी कमिश्नर तथा मनैजिंग डायरेक्टर सूरत सिटीलिंक लिमिटेड द्वारा प्रजेंटेशन दिया गया था।

कांग्रेस 14 नवंबर के बाद जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची

अहमदाबाद (ईएमएस)। प्रदेश कांग्रेस के उस दावे की हवा निकल गई है, जिसमें उसने दावा किया था कि वह जल्द ही अहमदाबाद समेत राज्यभर की 182 सीटों पर सक्षम उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। यूं तो कांग्रेस एक से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने का दावा करती है, परंतु चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी अब तक ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण है पास नेता हार्दिक पटेल, ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी की मांगें पूरी करना कांग्रेस के लिए अनिवार्य हो गया है। माना जा रहा है कांग्रेस 14 नवंबर के बाद अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी ने तीन दिनों तक उम्मीदवारों के चयन को लेकर लंबी चर्चा की है, इसके बावजूद पहली सूची जारी करने में विलंब हो रहा है। दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक

मेंउम्मीदवारों के चयन के अलावा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति, स्टार प्रचारक, संगठन के मुद्दों पर चर्चा की गई। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भरतसिंह सोलंकी, गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत समेत वरिष्ठ नेताओं के दिल्ली से लौटने के बाद आज से प्रदेश मुख्यालय में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में अधूरे काम को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बाला थोराट और उनकी टीम कल अहमदाबाद आएगी। अहमदाबाद में कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। पहले चरण में सौराष्ट्र और दक्षणि गुजरात की 89 सीटों के लिए आगामी 9 दिसंबर 2017 को मतदान होना है और इसके लिए आगामी 14 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर 2017 है। माना जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी।

पहली सूची में केवल सौराष्ट्र और दक्षणि गुजरात की सभी सीटों के बजाए जिला पंचायत और तहसील पंचायतों में कांग्रेस के वर्चस्व वाली महत्वपूर्ण सीटों के अलावा दूसरे चरण के चुनाव में उत्तर गुजरात व मध्य गुजरात की 93 सीटों के लिए 14 दिसंबर को होनेवाले चुनाव के संदर्भ में इन दोनों झोन की मजबूत सीटें शामिल होंगी। पार्टी हाईकमांड की पहली सूची में मौजूदा सभी विधायकों के नाम शामिल हो सकते हैं।

अहमदाबाद से गुजरनेवाली छह ट्रेनों में अतिरिक्त स्लीपर कोच

अहमदाबाद (ईएमएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की बढ़ी संख्या और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद से गुजरने वाली छह ट्रेनों में अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाए गए हैं। ट्रेन संख्या 12971/12972 बांद्रा-भावनगर एक्सप्रेस में 25 अक्टूबर को बांद्रा से 25 व 26 अक्टूबर को भावनगर से एक स्लीपर कोच अतिरिक्त रूप से लगेगा। ट्रेन संख्या 12905/12906 पोरबंदर-हावडा एक्सप्रेस में 25 व 26 अक्टूबर को पोरबंदर से तथा 27 व 28 अक्टूबर को हावडा से एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगा। ट्रेन संख्या 19269/19270 पोरबंदर-मुज्जफरपुर एक्सप्रेस में 26 अक्टूबर को पोरबंदर से और 29 अक्टूबर को मुज्जफरपुर से एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगा।

नरेन्द्र पटेल कैशकांड की चुनाव आयोग से शिकायत करेगी आप

अहमदाबाद (ईएमएस)। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति (पास) छोड़कर भाजपा में शामिल होनेवाले नरेन्द्र पटेल को लाखों रुपए देने के मामले की आम आदमी पार्टी (आप) चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। आप की गुजरात इकाई के प्रवक्ता हर्षिल नायक ने आरोप लगाया कि धन और सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव जीतने में भाजपा माहिर है। देशभर में विपक्ष के नेताओं को धन, डरा धमकाकर पार्टी में शामिल कराने के भाजपा के अनेक कारनामे अब तक सामने आ चुके हैं। गुजरात में भी आगामी चुनावों में हार देख भाजपा ने अपने नेताओं को खरीद फरोक्त में लगा दिया है। कुछ समय पहले पास नेता नरेन्द्र पटेल ने इस बारे में गंभीर खुलासा किया है। जिन्होंने भाजपा में शामिल होने के लिए एक करोड़ रुपए की ऑफर मिली होने के साथ ही टोकन स्वरूप रु. 10 लाख दिए जाने का आरोप भाजपा पर लगाया था। हर्षिल नायक ने बताया कि भाजपा ने यह काम पूर्व पास नेता वरूण पटेल को सौंपा था, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जीतु वाघाणी समेत अन्य नेता भी शामिल हैं। इस बात का पुष्टि करनेवाले एक ऑडियो कल वायरल हुआ था। वरूण पटेल पहले 60 प्रतिशत और भाजपा में शामिल होने के बाद 40 प्रतिशत रकम देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ऑडियो से भाजपा के भ्रष्ट कारगुजारियां जनता के सामने उजागर हो गई हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही मांगकर चुकी है कि वरूण पटेल, जीतु वाघाणी और भाजपा के अन्य नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। अब आप चुनाव आयोग के इस प्रकरण की शिकायत कर वरूण पटेल, जीतु वाघाणी समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करेगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आनेवाले दिनों में अपने अपने तरीकों से नेताओं की खरीद फरोख्त कर सकती है, जिस पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग को समय रहते कार्यवाही करनी चाहिए।

चुनाव के मौके पर सब्जियों की कीमतों में वृद्धि

अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले सब्जियों की कीमतों अचानक वृद्धि से गृहिणियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस साल सब्जियों की व्यापक बुवाई और उत्पादन के बावजूद कृत्रिम मूल्यवृद्धि आम लोग परेशान हैं। दीपावली के त्यौहारों में टमाटर, धनिया और गरीबों की कस्तूरी कही जाती प्याज के दाम आसमान छूने लगे थे, जिसकी वजह से गृहिणियों का बजट डगमगा गया था। हर दीवाली पर धनिया की कीमत प्रति किलो रु. 200 हो जाती है, इसके बावजूद आपूर्ति विभाग की ओर से इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की जाती। आम दिनों में टमाटर प्रति किलो रु. 15 से रु. 20 में उपलब्ध होते थे, जो अचानक बढ़कर रु. 50 प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। प्याज रु. 20 प्रति किलो और धनिया की कीमत प्रति किलो रु. 200 पर पहुंच गई है। टमाटर और प्याज कीमतें बढ़ने से ज्यादातर होटलों में सलाद मिलना बंद हो गया है। प्याज, धनिया और टमाटर की कीमतों में अचानक वृद्धि से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। व्यापारियों के मुताबिक टमाटर, प्याज और धनिया की आय कम हो रही है, जिसकी वजह से मनमानी दाम वसूले जा रहे हैं। पिछले डेढ महीने में हर दिन सब्जियों की कीमतें कम-ज्यादा होती रही हैं। जिसे लेकर गृहिणियां पहले से ही परेशान हैं। आनेवाले दिनों में प्याज, धनिया और टमाटर की कीमतें बढ़ने की संभावना जताई गई है। कई व्यापारियों के कालाबाजारी की वजह से सब्जियों की कीमतों में कृत्रिम वृद्धि हुई है। कालाबाजारियों पर लगाम नहीं लगाने की वजह से ये लोग मनमाने दाम वसूल रहे हैं।

आजादी के बाद कांग्रेस मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी : बाबू बोखीरिया

पोरबंदर। विवादित बयान देकर सूर्खियों में रहनेवाले गुजरात सरकार के मंत्री बाबू बोखीरिया की एक बार फिर जबान फिसली है। अबकि बार बोखीरिया पीएम मोदी की भक्ति में इस कदर लीन हो गए कि वे क्या बोल रहे हैं इसका उन्हें अहसास ही नहीं हुआ। दरअसल पोरबंदर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसे संबोधित करते हुए बाबू बोखीरिया ने कहा कि देश जब आजाद हुआ तब कांग्रेस भी चाहती थी कि नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनें। मोदी भक्ति में लीन बाबू बोखीरिया भूल गए कि भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और नरेन्द्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। कई दफा पीएम मोदी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिसका जन्म देश आजाद होने के बाद हुआ है। पीएम मोदी के अपने जन्म के बारे में दिए बयान को याद कर लेते तो आज उन्हें हंसी का पात्र नहीं बनना पड़ता। बोखीरिया ने अपने बयान में दावा किया कि कांग्रेस के सभी लोग मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थे।

आखिर भाजपा को याद आए जयनारायण व्यास और यमल व्यास

अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात में नरेन्द्र मोदी के शासनकाल के दौरान भाजपा के कई बुद्धिजीवियों को हासिए पर रख दिया गया था, लेकिन अब जबकि भाजपा चारों ओर से घिर गई है, तब पार्टी के पुराने दिग्गज नेता जयनारायण व्यास और यमल व्यास को प्रवक्ता नियुक्त करना पड़ा है। इनके अलावा भरत पंड्या, जगदीश भावसार, किरीट सोलंकी, पूनम माडम और आईके जाडेजा को भी प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। वर्षों तक भाजपा में सक्रिय रहे वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री जयनारायण व्यास और चार्टर्ड एकाउन्टन्ट यमल व्यास को पार्टी पिछले डेढ दशक से कोई तवज्जो नहीं दे रही थी। लेकिन अब चारों से ओर से घिरी भाजपा को मन से नहीं तो तर्क से बचाव करने वालों की जरूरत महसूस हुई है और यही वजह है कि जयनारायण व यमल व्यास को नियुक्त करना पड़ा है। केशूभाई पटेल की सरकार में मंत्री रहे और सालों तक गुजरात सरकार में सेवा प्रदान करनेवाले जयनारायण व्यास नरेन्द्र मोदी के गुजरात आने के बाद सरकार व संगठन से दूर हो गए थे। ऐसी ही स्थिति यमल व्यास की थी। व्यास सरनेमधारी जयनारायण और यमल पिछले डेढ़ दशक से राजनीतिक वनवास काट रहे थे। आज कांग्रेस जिस प्रकार कड़ी टक्कर दे रही है, तब भाजपा को आंकड़ों की मायाजाल समझ सकें ऐसे प्रवक्ताओं की जरूरत आन पड़ी है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा 4 ओ-ब्लाक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष सचीन रेल्वे स्टेश के पास,सूरत, जि. सूरत, गुजरात से प्रकाशित, एवं ताप्तीलोक पब्लिकेशन 152,153 श्री राम इंडस्ट्रीयल एरिया पांडेसरा सूरत 394210 से मुद्रत, फोन नं. 9879141480 संपादक सुरेश मौर्या (पी आर बी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी) E-mail: krantisamay@gmail.com